



# बिहार गजट

## असाधारण अंक

### बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

2 भाद्र 1939 (श10)

(सं0 पटना 747) पटना, वृहस्पतिवार, 24 अगस्त 2017

गृह विभाग  
(आरक्षी शाखा)

अधिसूचना  
23 अगस्त 2017

सं० 4/वि1-10-37/2016-6836/गृ0आ0—बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग अधिनियम 2016 की धारा-14 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल बिहार पुलिस एवं अन्य विभागों के विशिष्ट वर्दीधारी समूह-‘ग’ के विभिन्न पदों पर भर्ती की अनुशंसा के लिए बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग के गठन हेतु निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :-

1. **संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारंभ।**—(1) यह नियमावली ‘बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग नियमावली, 2017’ कही जा सकेगी।
  - (2) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा।
  - (3) यह तुरंत प्रवृत्त होगी।
2. **परिभाषाएं।**— इस नियमावली में, जब तक विषय या संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो—
  - (i) ‘सरकार’ से अभिप्रेत है बिहार राज्य सरकार;
  - (ii) ‘विभाग’ से अभिप्रेत है गृह विभाग (आरक्षी शाखा), बिहार, पटना;
  - (iii) ‘अधिनियम’ से अभिप्रेत है बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग 2016 (बिहार अधिनियम सं० 16);
  - (iv) ‘आयोग’ से अभिप्रेत है इस अधिनियम के अधीन गठित बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग और इसमें इसके अध्यक्ष एवं सभी अन्य सदस्य शामिल हैं:  
परंतु किसी सदस्य की छुट्टी या अन्यथा अनुपस्थिति की दशा में अध्यक्ष एवं शेष सदस्यों को मिलाकर आयोग गठित समझा जायेगा ;
  - (v) ‘अध्यक्ष’ से अभिप्रेत है अधिनियम की धारा-3 के अधीन राज्य सरकार द्वारा नियुक्त बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग का अध्यक्ष ;
  - (vi) ‘सदस्य’ से अभिप्रेत है अधिनियम की धारा-3 के अधीन राज्य सरकार द्वारा नियुक्त बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग के सदस्य ;

- (vii) 'सेवा एवं संवर्ग' से अभिप्रेत है कोई सेवा या संवर्ग जिसमें नियुक्ति हेतु अधिनियम की धारा-8 के अधीन आयोग की अनुशंसा की अपेक्षा हो;
- (viii) 'पद' से अभिप्रेत है कोई पद जिसमें नियुक्ति हेतु अधिनियम की धारा-8 के अधीन आयोग की अनुशंसा की अपेक्षा हो;
- (ix) 'सचिव' से अभिप्रेत है राज्य सरकार द्वारा नियुक्त आयोग का सचिव और इसमें वह पदाधिकारी भी शामिल है जो सचिव की अनुपस्थिति में सचिव का कार्य निष्पादित करने हेतु अध्यक्ष द्वारा प्राधिकृत किया जाये।
3. **आयोग के अध्यक्ष की प्रास्थिति, वेतन एवं सुविधाएँ।—**
- (1) सरकार पुलिस महानिदेशक/अपर पुलिस महानिदेशक स्तर के सेवानिवृत्त अथवा सेवारत पदाधिकारी को आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त/नामित कर सकेगी।
- (2) आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त/नामित सेवारत पदाधिकारी को अपना पदीय वेतन एवं विभागीय सचिव को अनुमान्य सभी सुविधाएँ उपलब्ध होंगी।
- (3) आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त सेवा निवृत्त पदाधिकारी को अपने सेवा काल के अंतिम वेतन के बराबर पदीय वेतन एवं विभागीय सचिव को अनुमान्य सभी सुविधाएँ अनुमान्य होंगी।
- फिर भी, यदि कोई पदाधिकारी अपनी सेवा निवृत्ति के बाद आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया जाता है, तो वह अपनी नियुक्ति की तिथि से, सेवा निवृत्ति के बाद सेवा निवृत्ति की तिथि से प्राप्त पेंशन की राशि (जिसमें पेंशन का वह भाग जो सारांशीकृत (कम्यूटेड) किया जाता हो, शामिल हो) और अपनी पूर्व सेवा के लिए अन्य सेवान्त लाभों के समतुल्य राशि को घटाने के बाद शेष राशि वेतन के रूप में पायेगा।
4. **आयोग के सदस्य का स्तर, वेतन एवं सुविधाएँ।—**
- (1) (क) राज्य सरकार पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस उप-महानिरीक्षक/पुलिस अधीक्षक स्तर के सेवानिवृत्त या सेवारत दो अधिकारियों को आयोग के सदस्य के रूप में नियुक्त कर सकेगी।
- (ख) उक्त दो सदस्यों में से एक सदस्य को अध्यक्ष द्वारा "सदस्य-सचिव" के रूप में नामित किया जायेगा।
- (ग) विभाग अन्य विभागों, यथा गृह विभाग, पर्यावरण एवं वन विभाग, निबंधन, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग, परिवहन विभाग एवं आपदा प्रबंधन विभाग के संयुक्त सचिव से अन्यून स्तर के अधिकतम 2(दो) सदस्य नामित करेगा।
- उक्त सदस्यों में कम से कम एक सदस्य अल्पसंख्यक एवं एक सदस्य अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन-जाति के होंगे।
- (2) आयोग के सदस्य राज्य सरकार में कार्यरत समकक्ष पंक्ति के पदाधिकारियों को अनुमान्य वेतन एवं अन्य सभी सुविधाओं के पात्र होंगे।
- (3) आयोग के सदस्य के रूप में नियुक्त सेवा निवृत्त पदाधिकारियों को अपनी सेवा काल के अंतिम वेतन के बराबर पदीय वेतन एवं विभागीय सचिव को अनुमान्य सभी सुविधाएँ प्राप्त होंगी।
- फिर भी, यदि कोई पदाधिकारी अपनी सेवा निवृत्ति के बाद आयोग के सदस्य के रूप में नियुक्त किया जाता है, तो वह अपनी नियुक्ति की तिथि से सेवा निवृत्ति के बाद सेवा निवृत्ति की तिथि से प्राप्त पेंशन की राशि (जिसमें पेंशन का वह भाग जो सारांशीकृत (कम्यूटेड) किया जाता हो, शामिल हो) और अपनी पूर्व सेवा के लिए अन्य सेवान्त लाभों के समतुल्य राशि को घटाने के बाद शेष राशि वेतन के रूप में पायेगा।
- (4) अध्यक्ष/सदस्य के पद पर नियुक्ति के बाद वेतन पुनरीक्षण होने की स्थिति में जिस Matrix के अनुसार सेवारत/सेवानिवृत्त कर्मियों का वेतन पुनरीक्षण होगा, उसी Matrix में इनका वेतन भी पुनरीक्षित हो जायेगा।
5. **आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की छुट्टी।—** अध्यक्ष एवं सदस्यों की छुट्टी मंजूर करने की प्रक्रिया वही होगी जो समकक्ष पंक्ति के पदाधिकारियों पर लागू हो। अध्यक्ष की छुट्टी या अन्यथा अनुपस्थिति में वरिष्ठतम सदस्य अध्यक्ष के प्रशासनिक कार्यों का प्रभार धारण करेगा।
6. **आयोग के कार्य एवं अधिकार।—**
- (i) अधिनियम की धारा-8 के अनुसार आयोग इस अधिनियम की अनुसूची में यथा सम्मिलित रू० 4200/- (चार हजार दो सौ) ग्रेड-पे अथवा समय-समय पर यथा पुनरीक्षित समरूप ग्रेड-पे/वेतनमान से कम ग्रेड-पे/वेतनमान वाले राज्य सरकार के विभिन्न विभागों, संलग्न कार्यालयों एवं क्षेत्रीय कार्यालयों में समूह 'ग' के सभी विशिष्ट वर्दीधारी संवर्ग एवं पदों, जिसमें विहित शारीरिक जाँच एवं दक्षता परीक्षण शामिल हों, एवं अन्य पदों पर नियुक्ति हेतु चयन एवं अनुशंसा कर सकेगा।
- (v) आयोग की अनुशंसा विभाग में उसकी प्राप्ति की तिथि से एक वर्ष के लिए विधिमान्य होगी :

परंतु, आयोग को अपनी अनुशंसा अगले एक वर्ष के लिए पुनः विधिमान्य करने की शक्ति होगी।

7. **आयोग के कार्यों का संव्यवहार।**— इस नियमावली की अनुसूची-1 एवं 2 में यथा निर्दिष्ट कार्यों का संव्यवहार क्रमशः आयोग एवं आयोग के अध्यक्ष द्वारा किया जायेगा।
8. **आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों के कार्य एवं उत्तरदायित्व।**—
  - (1) आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों द्वारा नियमावली की अनुसूची-1 में उल्लिखित कार्यों का निष्पादन किया जायेगा। इसी प्रकार आयोग के अध्यक्ष द्वारा अनुसूची-2 में अंकित कार्यों का निष्पादन किया जायेगा।
  - (2) आयोग का अध्यक्ष आयोग के सदस्यों में से किसी एक सदस्य को परीक्षा नियंत्रक का उत्तरदायित्व एवं अन्य सदस्यों में से किसी एक सदस्य को प्रशासनिक शाखा का उत्तरदायित्व सौंप सकेगा। आयोग के अन्य सदस्य अध्यक्ष के परामर्श से अन्य उत्तरदायित्वों का पालन करेंगे।
9. **आयोग की बैठकों की कार्यवाहियाँ।**—
  - (1) आयोग के सभी निर्णयों का अभिलेखन बैठक में ही सचिव या अध्यक्ष द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य पदाधिकारी द्वारा किया जायेगा। यदि कोई सदस्य किसी निर्णय का विरोध प्रकट करे तो उसे कार्यवाही में अभिलिखित किया जायेगा। मत-भिन्नता की दशा में बहुमत द्वारा निर्णय लिया जायेगा।
  - (2) बैठक की कार्यवाही की संपुष्टि आयोग की अगली बैठक में की जायेगी।
  - (3) आयोग के निर्णयों का संसूचन सचिव/अध्यक्ष द्वारा प्राधिकृत किसी पदाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित पत्र से किया जायेगा।
  - (4) आयोग की कार्यवाहियाँ गोपनीय होंगी और उन्हें आयोग की अनुमति के बिना संसूचित नहीं किया जायेगा।
10. **वित्तीय शक्तियाँ।**—
  - (1) बजट आवंटन के भीतर मोटरगाड़ी क्रय को छोड़कर कार्यालय-प्रशासन व्यय को मंजूर करने की शक्ति आयोग को होगी :
 

परंतु, परीक्षा संचालन के लिए क्रय, संविदा एवं अन्य विभागीय क्रय करने, संविदा निष्पादित करने और कार्यालय प्रशासन के लिए किसी अन्य व्यय को मंजूर करने की पूर्ण शक्ति आयोग को होगी। अन्य आकस्मिक व्यय के लिए अध्यक्ष को बिहार वित्त नियमावली के नियम-110(2) के अधीन शक्ति प्राप्त होगी।
  - (2) बिहार कोषागार संहिता के नियम-177 में अभिकथित निबंधनों एवं शर्तों के अनुसार, परीक्षा संचालन के लिए कोषागार से ₹00 100000.00 (एक लाख ₹00) से अधिक धन की अग्रिम तथा निकासी को मंजूरी देने की शक्ति आयोग को होगी। एक लाख रुपये तक यह शक्ति आयोग के अध्यक्ष को होगी। क्रय से संबंधित मामलों में, अग्रिम धन की निकासी तभी की जायेगी जब अनुमोदित निविदा में ऐसी शर्त हो।
  - (3) प्रश्न पत्रों की छपाई एवं उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन पर होने वाले/हुए व्यय के संबंध में बिहार वित्त नियमावली भाग-2 परिशिष्ट-5 की मद सं0- 39 में अभिकथित प्रक्रिया लागू होगी।
  - (4) आयोग द्वारा किया जाने वाला व्यय मुख्य मुख्य शीर्ष-2051-लोक सेवा आयोग, उप मुख्य शीर्ष-00-, लघु शीर्ष-103-कर्मचारी चयन आयोग, उप शीर्ष-0003-बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग, विपत्र कोड-N2051001030003 के अधीन, विकलनीय होगा।
  - (5) आयोग राज्य सरकार से प्राप्त राशि और विविध रसीदों द्वारा प्राप्त राशि को बैंक खाता खोलकर रखेगा। अभ्यर्थियों से प्राप्त फीस के लिए एक पृथक बैंक खाता होगा और यह राशि तुरंत और माह के अंत तक राजकोष में प्राप्त-मुख्य 'मुख्य शीर्ष-0051-लोक सेवा आयोग, उप मुख्य शीर्ष-00-, लघु शीर्ष-105-राज्य लोक सेवा आयोग परीक्षा शुल्क, उप शीर्ष-0004-बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग परीक्षा शुल्क', विपत्र कोड-R0051001050004 के अधीन जमा की जायेगी। प्रत्येक वर्ष ऐसी फीस के रूप में प्राप्त राजस्व का ब्योरा विभाग को भेजा जायेगा।
11. **आयोग के पदाधिकारी/कर्मचारी।**—
  - (1) आयोग के कार्य संचालन हेतु अधीनस्थ पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों का पद बल वही होगा जो सरकार द्वारा समय-समय पर मंजूर किया जाय। मंजूर किये गये पद बल के विरुद्ध सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा पदाधिकारी/कर्मचारी उपलब्ध कराये जायेंगे। कतिपय पदों, यथा-आदेशपाल, चालक, सहायक, कम्प्यूटर प्रोग्रामर, कम्प्यूटर ऑपरेटर पर नियमित नियुक्ति होने तक आयोग द्वारा किसी संस्था के माध्यम से सरकार/बेल्ट्रान द्वारा नियत वेतन पर संविदा के आधार पर सेवा ली जा सकेगी।

- (2) नियमित रूप से नियुक्ति/पदस्थापित आयोग के पदाधिकारियों/कर्मचारियों की सेवा शर्तें वही होंगी जो समकक्ष स्तर के सरकारी सेवकों पर लागू हों। आयोग के पदाधिकारियों/कर्मचारियों पर अनुशासनिक कार्रवाई संबंधी वे ही नियम/संकल्प/परिपत्र लागू होंगे जो सरकार के उनके स्तर/सेवा के पदाधिकारियों/कर्मचारियों पर लागू हैं।
- (3) सरकार द्वारा, समय-समय पर, स्वीकृत पद बल के अतिरिक्त आवश्यकतानुसार परीक्षा-प्रक्रिया के सुचारू रूप से संचालन के लिए आयोग विज्ञापन के आधार पर बाह्य व्यक्तियों की सेवा, विनिर्दिष्ट अवधि के लिए, संविदा पर ले सकेगा और परीक्षा-प्रक्रिया समाप्त हो जाने के बाद उनकी सेवा तुरंत समाप्त कर देगा। ऐसे रखे गये व्यक्तियों की संख्या एवं उन्हें भुगतये राशि की दर पर आयोग सरकार का पूर्व अनुमोदन प्राप्त कर लेगा।

#### 12. वित्तीय प्रावधान।—

- (1) आयोग की स्थापना पर होने वाले वार्षिक व्यय का वहन विभाग द्वारा अपने बजट शीर्ष के अधीन आवश्यक निधि उपबंध कर किया जायेगा।
- (2) आयोग प्रत्येक वर्ष का बजट प्राक्कलन तैयार करेगा और विभाग को भेजेगा ताकि विभाग के बजट के अधीन उसको सम्मिलित किया जा सके।

**13. व्यय पर नियंत्रण।—** आयोग के नियंत्री पदाधिकारी व्यय पर नियंत्रण करेंगे तथा बिहार वित्त नियमावली के नियम 471 से 479 के अधीन प्रदत्त उत्तरदायित्वों का निष्पादन करेंगे। लेखा का संधारण एवं उनका अंकेक्षण सरकार द्वारा विहित प्रक्रिया के अनुसार ही किया जायेगा। इससे संबद्ध सुसंगत जानकारी तथा प्रतिवेदन आयोग के द्वारा विभाग (आरक्षी को समय-समय पर उपलब्ध कराया जायेगा।

#### अनुसूची-1

#### आयोग द्वारा सम्बन्धित किये जाने वाले कार्य

- (i) आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन।
- (ii) अधिनियम की धारा 14(2) के अधीन निर्मित नियमावली के तहत परीक्षा की स्कीम एवं पाठ्यक्रम।
- (iii) सभी मामले जिनमें नयी नीति हेतु प्रस्ताव तैयार कर सरकार को भेजना हो।
- (iv) कोई मामला जिसमें वर्तमान नीति को संशोधित/पुनरीक्षित करने हेतु प्रस्ताव तैयार कर सरकार को भेजना हो।
- (v) वे मामले जिनमें पद एवं सेवाओं में भर्ती के लिए प्रतियोगिता परीक्षा संचालित करने हेतु विनियमावली बनाने के संबंध में निर्णय लेने की आवश्यकता हो;
- (vi) कोई मामले जिसमें भर्ती नियमावली नहीं बनी है और उनमें आयोग को चयन की प्रक्रिया का निर्धारण करना हो;
- (vii) आयोग के कार्यों के निष्पादन हेतु कार्य संचालन विनियमावली का प्रारूप, सरकार के अनुमोदन हेतु भेजना;
- (viii) आयोग की अधिकारिता से हटाने एवं आयोग के कार्यों के विस्तार का प्रस्ताव तैयार कर सरकार के अनुमोदन हेतु भेजना;
- (ix) परीक्षा पद्धति के अनुसंधान से संबंधित विषय;
- (x) साक्षात्कार/अन्तर्वीक्षा पर्वद के गठन हेतु पैनल का निर्माण ;
- (xi) परामर्शियों/विषेषज्ञों के चयन हेतु पैनल का गठन एवं बोर्ड की संरचना;
- (xii) अन्तर्वीक्षा की तिथियों को नियत करना;
- (xiii) परीक्षा की तिथियों, परीक्षाओं एवं मूल्यांकन स्थानों का नियत करना;
- (xiv) अधिवक्ताओं के पैनल का गठन;
- (xv) भर्ती के लिए अधिसूचना/विज्ञापन और समाचार पत्रों का चयन करना जिसमें विज्ञापन प्रकाशित किये जाने वाले हों;
- (xvi) परीक्षा तथा अन्तर्वीक्षा के परिणामों (परीक्षाफलों) का अनुमोदन;
- (xvii) पद्धति विकास और डाटा प्रासेसिंग एवं इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग शाखा संबंधी तकनीकी पहलु वाले अन्य कार्य;
- (xviii) उम्मीदवारों के आवेदन पर उत्तर पुस्तिकाओं की पुनःसमीक्षा का निर्णय;
- (xix) कोई अन्य मामला जिसे विचार एवं निर्णय हेतु अध्यक्ष आयोग के समक्ष रखना चाहें;
- (xx) कोई अन्य मामला जो इस नियमावली में आच्छादित न हो उस पर प्रस्ताव तैयार कर सरकार के अनुमोदन हेतु भेजना हो।

अनुसूची-2  
अध्यक्ष द्वारा निष्पादित किये जाने वाले कार्य :-

- (i) आयोग का सामान्य प्रशासन;
- (ii) आयोग की बैठक आहूत करने सहित आयोग के कार्य का समन्वय;
- (iii) आयोग के सदस्यों को आयोग के कार्यों का आवंटन ;
- (iv) अध्यक्ष द्वारा मनोनीत किसी सदस्य को कोई संचिका परीक्षण के लिए पृष्ठांकित करना;
- (v) प्राश्निकों (प्रश्न चयनक), मर्यादकों (मोडरेटर्स/परीक्षकों) की नियुक्ति;
- (vi) प्रश्न पत्रों के मुद्रण का अनुमोदन;
- (vii) आवश्यकतानुसार या जनहित में यदि अध्यक्ष उचित समझे तो किसी खास मामले या कार्य को निष्पादनार्थ आयोग के समक्ष प्रस्तुत करने का निदेश दे सकेगा;
- (viii) न्यायिक मामलों के लिए तथ्य विवरणी की जॉच/शपथ-पत्र दाखिल करना;
- (ix) आयोग द्वारा तैयार पैनल से बोर्ड का गठन एवं साक्षात्कार/अन्तर्वीक्षा तिथियों का अवधारण।
- (x) आयोग द्वारा स्वीकृत पैनल से वकीलों को कार्य पर रखना।
- (xi) आयोग द्वारा समय-समय पर कार्यहित में सौंपे गये कार्यों का निष्पादन।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,  
रंजन कुमार सिन्हा,  
सरकार के अपर सचिव।

23 अगस्त 2017

सं० 4/वि०1-10-37/2016-6836, दिनांक 23 अगस्त 2017 द्वारा अधिसूचित बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग नियमावली, 2017 का निम्नलिखित अंगरेजी अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है जिसे भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड-(3) के अंतर्गत अंगरेजी भाषा में उक्त नियमावली का प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,  
रंजन कुमार सिन्हा,  
सरकार के अपर सचिव।

*The 23<sup>rd</sup> August 2017*

No-4/B1-10-37/2016-6836/H.P—In exercise of the powers conferred under section-14 of the Bihar Police Sub-ordinate Services Commission Act, 2016 the Governor of Bihar is pleased to make the following Rules for the constitution of The Bihar Police Sub-ordinate Services Commission for recommendation of appointment to the various posts of Group-C having designated uniform of the Bihar Police and other Departments:-

1. **Short title, extent and commencement.**— (1) These rules may be called “The Bihar Police Sub-ordinate Services Commission Rules, 2017.”

(2) It shall extend to the whole of the State of Bihar.

(3) It shall come into force at once.

2. **Definition.- In these Rules, unless otherwise requires in the context -**

(i) “State Government” means the State Government of Bihar;

(ii) “Department” means the Home Department (Police Branch);

(iii) “Act” means the Bihar Police Sub-ordinate Services Commission Act, 2016 (Bihar Act No- 16);

(iv) “Commission” means the Bihar Police Sub-ordinate Services Commission and it includes its Chairman and all the other Members:

Provided that in case of absence of any Member on leave or otherwise, the Commission shall be deemed to be constituted comprising of the Chairman and rest members;

- (v) "Chairman" means the Chairman of the Bihar Police Sub-ordinate Services Commission appointed by the State Government under section-3 of the Act;
- (vi) "Member" means a Member of the Bihar Police Sub-ordinate Services Commission appointed by the State Government, under section-3 of the Act;
- (vii) "Service and Cadre" means a service or a cadre in which for appointment, the recommendation of the Commission is required under section-8 of the Act;
- (viii) "Post" means any post to which for appointment, the recommendation of the Commission is required under section-8 of the Act;
- (ix) "Secretary" means the Secretary of the Commission appointed by the State Government and it includes the officer authorized by the Chairman to perform the function of the Secretary, in the absence of the Secretary.

**3. Status, Pay and facilities of the Chairman of the Commission:-**

- (1) Government may appoint/ nominate serving or retired officer of the rank of Director General of Police/ Additional Director General of Police to the post of the Chairman of the Commission.
- (2) Serving officer, appointed/nominated as the Chairman of the Commission, shall be provided the pay of his post and all facilities admissible to a Departmental Secretary.
- (3) Pay equivalent to last pay of his service period and all facilities admissible to a Departmental Secretary shall be provided to retired officer appointed as the Chairman of the Commission.

However, if an officer after his retirement is appointed as the Chairman of the Commission, he will be paid as salary from the date of his appointment, after deducting the amount of pension, which he is to get after retirement from the date of retirement (including that part of the pension which has been commuted) and the amount equivalent to other retrial benefit from his earlier service.

**4. Status, Pay and facilities of the Member of the Commission. —**

- (1) (a) The State Government may appoint/ nominate two serving or retired officer of the rank of Inspector General of Police/ Deputy Inspector General of Police/ Superintendent of Police to the posts of the Members of the Commission.
- (b) One of the two Members will be nominated as the 'Member-Secretary' by the Chairman.
- (c) Department shall nominate maximum 2 (Two) Members, not below the rank of Joint Secretary, from other departments such as, Home Department, Environment and Forest Department, Registration, Excise & Prohibition Department, Transport Department and Disaster Management Department.

At least one member shall be from Scheduled Caste/Scheduled Tribe in the said Members.

- (2) Members of the Commission, shall be eligible for the pay and all the facilities admissible to the officers of equivalent rank working in the state government.
- (3) Pay equivalent to last pay of his service period and all facilities admissible to a departmental secretary shall be provided to a retired officer appointed as member of the Commission.

However, if an officer after his retirement is appointed as the Member of the Commission, he will be paid as salary from the date of his appointment, after deducting the amount of pension, which he is to get after retirement from the date of retirement (including that part of the pension which has been commuted) and the amount equivalent to other retrial benefit from his earlier service.

- (4) In case of pay revision after the appointment of Chairman/ Members, the pay of Chairman/ Members shall be revised in the same Matrix in which pay of working/ retired employees is revised.

5. **Leave to the Chairman and the Members of the Commission.**—The procedure for sanction of leave to the Chairman and the Members of the Commission shall be the same as applicable to the officers of the equivalent rank. In the absence of the Chairman on leave or otherwise, the senior most Member shall hold the charge of the administrative work of the Chairman.

6. **Power and functions of the commission.**—

- (1) As per Section-8 of the Act, the Commission may select and recommend for appointment to all cadres and posts of Group-C having designated 'Uniform' and prescribed physical ability and efficiency tests as well as such other posts having maximum Grade Pay upto Rs. 4200/- in the different departments under the State Government as mention in the appended Schedule of the Act.
- (2) The recommendations of the Commission will be valid for one year with effect from the date of its receipt in the Department.

Provided the Commission shall have power to revalidate its recommendation for further one year.

7. **Transaction of Business of the Members of the Commission.**—The transaction of business as specified in Schedule-1 and 2 of these Rules shall be made by the Commission and the Chairman of the Commission respectively.

8. **Functions and Responsibility of the Members of the Commission:**—

- (1) The Business mentioned in Schedule-1 of these Rules shall be executed by the Chairman and the Members of the Commission. Likewise, the business mentioned in Schedule-2 shall be executed by the Chairman of the Commission.
- (2) The Chairman of the Commission may entrust the responsibilities of the Examination Controller to any one of the Members and the responsibilities of the Administrative Section to any one of the other Members. Other Members of the Commission shall perform the other responsibilities, in consultation with the Chairman.

9. **Proceeding of the Meetings of the Commission.**—

- (1) All decisions of the Commission shall be recorded in the meeting by the Secretary or any other officer authorised by the Chairman. If any Member dissents any decision, it shall be recorded in the proceeding. In case of difference of opinion the decision shall be taken by majority.
- (2) The proceeding of the meeting shall be confirmed in the next meeting of the Commission.
- (3) The decisions of the Commission shall be communicated by a letter signed by the Secretary or by an officer authorised by the Chairman.
- (4) The proceedings of the Commission will be confidential and will not be communicated without the permission of the Commission.

10. **Financial Powers.**—

- (1) Within the budget allocation, the Commission shall have the power to sanction expenditure for office administration except purchase of a motor vehicle.

Provided that the Commission shall have full power to purchase for conducting the examinations and other departmental purchase to execute the contract and to sanction any other expenditure for office administration. For the contingent expenses, the Chairman shall have powers under rule 110(2) of the Bihar Financial Rules.

- (2) The Commission shall have power to sanction the advances and withdrawals of money more than Rs. (1,00,000/-) One Lakh from treasury for conducting of examination as per the terms and conditions laid down in Rule-177 of Bihar Treasury Code. The Chairman of the Commission shall have this power up to Rs. One Lakh. In cases related to purchase, advance money shall be drawn from treasury only when there is such condition in the approved tender.

- (3) Procedure laid down in item 39 of appendix 5 of the Bihar Financial Rules Part-II shall be applicable in the matters related to expenditure to be incurred on printing of question papers and evaluation of answer sheets.
- (4) Expenditure by the Commission shall be deductible under Major Head-2051-Public Service Commission, Sub Major Head -00- Minor Head- 103- Staff Selection Commission, Sub Head-0003- Bihar Police Sub-ordinate Services Commission, Bill Code-N2051001030003.
- (5) The Commission shall keep the amount received from Government and the amount received by miscellaneous receipts in a bank by opening an account. There shall be separate bank account for the fees received from the candidates and this amount shall be deposited in the treasury under Major Head-0051-Public Service Commission, Sub Major Head -00- Minor Head- 105- State Public Service Commission Examination Fee, Sub Head-0004- Bihar Police Sub-ordinate Services Commission Examination Fee, Bill Code- R0051001050004 immediately by the end of the month. The detail of the revenue received as fee shall be sent to the Department every year.

**11. *Officers and Staff of the Commission.*—**

- (1) Strength of posts of the subordinate officers and staff for conducting work of the Commission shall be the same as may be sanctioned by the Government, from time to time. Officers and staff shall be made available by the General Administration Department against approved sanctioned strength of the posts. The Service of certain posts, like- peon, driver, computer programmer, computer operator shall be taken by the Commission on the basis of contract from any institution at fixed pay, fixed by the Government/Beltron till the regular appointment.
- (2) The Conditions of service of the Officers and Staff of the Commission shall be the same which are applicable to the Government servants. The rules, resolutions, orders regarding disciplinary action as applicable to the Government servants of equivalent rank shall be applicable to the Officers and Staff of the Commission.
- (3) The Commission may engage on contract the services of persons for specified period for smooth conduct of examinations in addition to the post sanctioned by the Government on the basis of advertisement and the Commission shall terminate their services as soon the examination procedure is over. The Commission shall obtain the prior approval of the State Government on the number of such persons to be engaged and on the rate of the amount payable to them.

**12. *Financial provisions.*—**

- (1) Annual expenditure to be incurred on establishment of the Commission shall be borne by the Home Department (Police Branch) by providing the required fund under its budget head.
- (2) The Commission shall prepare the budget estimates every year and send it to the Department so that it may be included in the budget of the Department.

**13. *Control on expenditure.*—** The Controlling officer of the Commission shall control over the expenditure and perform the responsibilities conferred under Rules 471 to 479 of the Bihar Financial Rules. Maintenance of account and its audit will be made as per the procedure prescribed by the State Government. Relevant information and reports in this regard shall be made available by the Commission to the Department, from time to time.



**SCHEDULE-1**

**BUSINESS TO BE TRANSACTED BY THE COMMISSION.**

- (i) Annual report of the Commission;
- (ii) Scheme of Examinations and syllabus under Rules made under section 12(2) of the Act;
- (iii) All cases in which a new policy is required to be formulated for submission to Government;
- (iv) Any case in which the existing policy is required to be amended/revised for submission to Govt;
- (v) Such cases in which a decision is required to be taken regarding framing of the rules for holding Competitive Examinations for recruitment to posts and services;
- (vi) Any case in which recruitment rules have been framed and the Commission has to formulate the procedure of recruitment;
- (vii) Submit draft of work conduct regulation of the Commission for transacting of business to the Government;
- (viii) Submit proposals for exclusion from the jurisdiction of the Commission or extension of function of the Commission for the approval of the Government;
- (ix) Subjects related to research of Examination Method;
- (x) Preparation of panel for constitution of Interview Board;
- (xi) Preparation of panel of Advisors/Experts and structure of the Board;
- (xii) Fixing the dates of interview;
- (xiii) Fixing the dates of examination and centres of examination and the venue of evaluation centres;
- (xiv) Constitution of panel of Advocates;
- (xv) Advertisement and notification for recruitment and selection of newspapers in which advertisements are to be published;
- (xvi) Approval of results of examinations and interview;
- (xvii) System development and other works pertaining to technical aspect of Data processing and Electronic Data Processing Branch;
- (xviii) Review of answer books on application of candidates;
- (xix) Any other matter which the chairman places before the Commission for consideration and decision;
- (xx) Any other matter not covered by these rules and to be sent to the Government for approval after drafting the proposal;

**SCHEDULE-2**

**BUSINESS TO BE EXECUTED BY THE CHAIRMAN**

- (i) General administration of the Commission;
- (ii) Co-ordination of works of the Commission including convening the meeting of the Commission;
- (iii) Allocation of business amongst the members;
- (iv) Endorsement of any file for examination to any member nominated by the Chairman;
- (v) Appointment of paper-setters, moderators and examiners;
- (vi) Approval of printing of question papers;
- (vii) The Chairman may place any specific matter before Commission for disposal as per necessity or in public interest;
- (viii) Scrutiny of statement of facts or filing of affidavit in the courts cases;

- (ix) Constitution of Board from the panel approved by the Commission and fixing the dates of interview;
- (x) Power to engage the advocates from the panel approved by the Commission;
- (xi) Matter entrusted by the Commission from time to time in the interest, of the work.

By order of the Governor of Bihar,  
RANJAN KUMAR SINHA,  
*Additional Secretary to Government.*

—  
अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,  
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,  
बिहार गजट (असाधारण)747-571+200-डी0टी0पी0।  
Website: <http://egazette.bih.nic.in>